

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोन:- 2200660 फैंक्स : 0151-2527371 वर्ष: 46 संख्या: 265 प्रभात बीकानेर, शुक्रवार 18 अप्रैल, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

गुरुवार को दोपहर में राहुल गांधी बॉस्टन के लिए रवाना हो गये

राहुल गांधी बॉस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को सम्बोधित करेंगे, प्रवासी भारतीयों व फ्रैन्ड्स ऑफ कांग्रेस के सदस्यों से मुलाकात करेंगे

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। राहुल गांधी, जो दिल्ली में यथासंभव कम ही समय गुजारते हैं, गुरुवार शाम अमेरिका के बोस्टन शहर के लिये रवाना हो गये, जबकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार, 19 अप्रैल को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें नैशनल हैरल्ड केस में राहुल तथा सोनिया गांधी के खिलाफ पेश की गई ईंडी की चार्जशीट के विरोध के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जाना है।

खड़गे ने मीटिंग में सभी एआईसीसी महासचिव, राज्य प्रभारी, सचिव, अग्रणी संगठनों के प्रमुख तथा विभाग प्रमुख बुलाये हैं।

खड़गे द्वारा बुलाई गई पिछली मीटिंग निराशाजनक रही थी, क्योंकि उसमें कई लोग उपस्थित नहीं हुये थे। अनुपस्थित रहे नेताओं में एआईसीसी महासचिव तथा संगठन-प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल भी शामिल थे, जो राहुल गांधी के दायें हाथ तथा उनके पीछे की तरह व्यवहार करते हैं, इसीलिये बहुत से कांग्रेस नेता उन्हें असली कांग्रेस

■ राहुल की यह अमेरिका यात्रा उल्लेखनीय इसलिए है, क्योंकि शनिवार को कांग्रेसाध्यक्ष खड़गे ने राज्यों के प्रभारी, महासचिवों, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों आदि की बैठक बुला रखी है।

■ इस बैठक में यह निर्णय लिया जायेगा नैशनल हैरल्ड के मसले में, सोनिया गांधी व राहुल गांधी को जो नोटिस दिया गया है, उसके संदर्भ में कैसे विरोध प्रदर्शन किया जाये।

■ बैठक बुलाना जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि पिछली बार विरोध के लिए जो प्रदर्शन आयोजित किये गये थे, वे काफी “फ्लॉप” रहे थे। तथा, कई दिग्गज नेता अनुपस्थित रहे थे। महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे, वे गुजरात में राहुल गांधी के साथ थे।

■ अतः यह अजीबोगरीब बात है, कि, सोनिया गांधी व राहुल गाँधी को मजबूती देने का कार्यक्रम तय करने के लिए आयोजित बैठक में स्वयं राहुल गांधी उपस्थित नहीं होंगे।

अध्यक्ष कहते हैं, क्योंकि अधिकांश निर्णय वे ही लेते हैं तथा खड़गे के निर्णयों को उलट भी देते हैं।

यह मीटिंग राहुल गांधी की

1950 के दशक के “हिन्दी-चीनी भाई-भाई” के नारे को दोहराना चाहता है चीन

पर, 1950 में भारत भोला, आदर्शवादी सोच से ओत-प्रोत, नया देश था, पर अब परस्थितियां भी बहुत बदल गई हैं

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। यह एक ऐसा कूटनीतिक संकेत है जो प्रतीकात्मकता, सही समय और राजनीतिक इरादे से भरा हुआ है। भारत की तरफ चीन की हालिया पहल, जैसे वीजा प्रक्रियाओं को आसान बनाना, भारतीय पर्यटकों के लिए शुल्क में कटौती और सांस्कृतिक निमंत्रण देना आदि के बारे में कहा जा रहा है कि ये पैन्डेमिक के बाद के सामान्य आर्थिक प्रयास हैं, जिनका उद्देश्य पर्यटन तथा लोगों के बीच सम्पर्क को बढ़ावा देना है, लेकिन सतह से थोड़ा नीचे जाएं तो स्पष्ट होता है कि इन पहलों में उस बीते युग की गुंज है, जब भारत और चीन ने अपने आपको “हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारे के तहत, एशियाई भाईचारे के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की थी।

1950 के दशक की शुरुआत में

जल्द शुरु होगी कैलाश-मानसरोवर यात्रा

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल। भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने को लेकर जारी तकनीकी बातचीत पूरी हो गई है और जल्द ही सरकार यात्रा को शर्तें और अन्य विवरण सार्वजनिक करेगी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को यहां नियमित ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा

■ भारत और चीन के बीच इस संबंध में चल रही तकनीकी वार्ता पूरी हो गई है। जल्दी ही नोटिस जारी कर घोषणा की जा सकती है।

कि भारत सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर जल्दी ही एक नोटिस जारी करेगी। दोनों देशों के बीच यात्रा के तौर तरीकों और शर्तों आदि को लेकर जारी तकनीकी बातचीत में सहमति बन गई है। यह पृष्ठ जाने पर कि लद्दाख में डेमचोक के रास्ते से कैलाश मानसरोवर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। जब राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इस महीने के आरम्भ में रैसिप्रोकल टैरिफ नीति की शुरुआत की, तो वैश्विक बाजारों में कई व्यापारिक साझेदार देशों से आयात होने वाले उत्पादों पर 10 से 125 प्रतिशत ड्यूटी लगाई गई, जिसका तत्काल विरोध हुआ और बाजारों में उथल-पुथल मच गई। लेकिन इस दुस्साहसी कदम के पीछे जो नाम सबसे प्रमुख था, वह था पीटर नवारो, जो लम्बे समय से व्यापारिक संरक्षणवाद का पर्याय बना हुआ है।

ट्रेड और मैनुफैक्चरिंग के लिए

वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नवारो, ट्रंप के आक्रामक व्यापार हस्तक्षेपों के मुख्य शिल्पकार रहे हैं। प्रशासन की व्यापार नीतियों पर उनका गहरा प्रभाव न तो नया था और न ही संयोगवश। हार्वर्ड-प्रशिक्षित अर्थशास्त्री नवारो वर्षों से आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक रहे हैं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो वैश्विक व्यापार समझौतों की तुलना में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। चीन को आर्थिक खतरे के रूप में देखने की उनकी धारणा ने उन्हें ट्रंप की आर्थिक टीम में ऊंचे स्थान तक पहुंचाया, जहाँ उनकी संरक्षणवादी नीतियों ने अमेरिकी व्यापार संबंधों में बड़े बदलाव किए।

नवारो की विचारधारा की जड़ें

जयपुर, 17 अप्रैल। सत्र न्यायालय, जयपुर महानगर, प्रथम, ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी वसीम खान, मोहम्मद अशरफ और जुनैद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पीठासीन अधिकारी नंदिनी व्यास ने अपने आदेश में कहा कि जेल में रहते हुए इस तरह की षटना को अंजाम देना, सुरक्षा को चुनौती देने के

■ अदालत ने जेल में रहते धमकी देने को कानून व्यवस्था के लिए चुनौती देना माना।

समान है। आरोपियों पर जो आरोप लगाए गए हैं, वह कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले और समाज को आतंकित करने वाले हैं। यदि इन्हें जमानत दी गई तो मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। इसलिए इन्हें जमानत देना उचित नहीं है।

जमानत अर्जियों में कहा गया कि उन्होंने न तो पुलिस कंट्रोल रूम में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब तक किसे व कितनी विदेश शिक्षा छात्रवृत्ति दी गई

जयपुर, 17 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश कर यह बताने के लिए कहा है कि राजीव गांधी विदेश शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक किन-किन व्यक्तियों को कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में राज्य सरकार की ओर से दी गई है। अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि छात्रवृत्ति देते समय छात्रों की आर्थिक स्थिति क्या थी। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश कुमार मनजीत देवड़ा को याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने मामले को आगामी सुनवाई 21 अप्रैल को तय की है।

■ हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को शपथ पत्र के द्वारा जानकारी देने के निर्देश दिये।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के मेधावी और जरूरतमंद विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन कराने के लिए राजीव गांधी विदेश शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सभी मापदंड पूरा करने पर याचिकाकर्ता का चयन किया गया। वह करीब डेढ़ साल से ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रही है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक उसे इस योजना के तहत छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। जिसके चलते उसका प्रवेश रद्द हो सकता है और उसका वीजा भी समाप्त किया जा सकता है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार से योजना को संपूर्ण जानकारी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केन्द्रीय सरकार के वादे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित, वक्फ विधेयक पर “स्टे” नहीं दिया

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, संकेत दिये थे, कि वह विधेयक के कुछ प्रावधानों को “स्टे” करने की सोच रहा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिन पहले ऐसे संकेत दिये थे कि वह संशोधित वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर स्टे दे सकता है, लेकिन गुरुवार को न्यायालय ने वक्फ कानून में हाल ही में किये गये कुछ बदलावों पर स्टे नहीं दिया, क्योंकि केन्द्र ने अदालत को आश्वासन दे दिया कि वक्फ बोर्डों तथा कार्डसिलों में कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूज़र के रूप में घोषित या रजिस्टर्ड सम्पत्तियों को निर्दिष्ट (डिनेटिफाई) नहीं किया जायेगा।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केन्द्र की ओर से उपस्थित हुये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस आशय के बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया।

संक्षिप्त-सी सुनवाई के बाद, बेंच,

■ सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जजों के समुख तर्क रखा कि, “प्राइमा फेसिया” रीटिंग के बाद, संशोधित वक्फ विधेयक के प्रावधानों को “स्टे” करना उचित नहीं होगा।

■ मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने यह तर्क स्वीकार करते हुए, पर यह वादा भी मांगा सरकार से कि वक्फ बोर्ड में नवनियुक्तियां, वक्फ प्रॉपर्टी को चिन्हित करना, आदि कार्यवाही नहीं होगी सरकार की ओर से।

■ सॉलिसिटर जनरल के इस आश्वासन पर कि, सात दिनों में सरकार पूरी जानकारी इकट्ठी करके अपना जवाब पेश करेगी, तथा तब तक वर्तमान स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा, सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का “स्टे” नहीं दिया।

जिसमें जस्टिस संजय कुमार तथा के.वी. विश्वनाथन भी शामिल हैं, ने अपने आदेश में कहा कि सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

ने कहा कि “प्रतिवादी एक छोटा-सा जवाब देना चाहेंगे, जो सात दिन के अन्दर पेश कर दिया जायेगा।” “उन्होंने (मेहता) आगे कहा कि संशोधित

का मूल दर्शन, जो व्यापारिक घाटा कम करने, विदेशी व्यापार में जोड़-तोड़ का मुकाबला करने और अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करने पर आधारित है, ट्रंप प्रशासन द्वारा वर्ष 2025 में घोषित साहसी नीति का वैचारिक आधार बना।

अब यह सिर्फ़ एकैडमिक रुख नहीं रहा है। नवारो ने न केवल टैरिफ का समर्थन किया। बल्कि इस टैरिफ नीति के निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका थी और इसके पक्ष में बहुत ज्यादा मुखर भी थे। फरवरी 2025 में एक इंटरव्यू में नवारो ने इसे अन्यायपूर्ण व्यापार प्रक्रिया के खिलाफ सुधारात्मक उपाय बताते (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। पूर्व राॅ प्रमुख ए.एस. दुलत, जो अब्दुल्ला परिवार के नजदीक माने जाते हैं, ने अपने इस दावे से नैशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने दिग्गज डॉ. फारुक अब्दुल्ला को संकट में डाल दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री “दिल्ली की भाजपा सरकार के साथ काम करने की इच्छा को लेकर पूरी तरह खुले हुये थे” तथा जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने वाले विधेयक को पारित कराने में मदद तक कर सकते थे।

दुलत की नई पुस्तक “द चीफ मिनिस्टर एण्ड द स्प्याय” में किये गये रहस्योद्घाटनों ने एक नया और बड़ा राजनैतिक विवाद खड़ा कर दिया है। राज्य के विपक्षी नेता कह रहे हैं कि इस पुस्तक ने डॉ. अब्दुल्ला के चेहरे पर ‘बचे हुये अंतिम मुवौंटे को भी हटा’ दिया है। पीडीभी नेता तथा विधायक वहीदुर्रहमान परां ने कहा, “जो आग उगलने वाले भाषण, वो नाटकीय

■ दुलत कई वर्षों तक कश्मीर में भारत सरकार की इंटैलिजेंस एजेंन्सी ‘राॅ’ के मुखिया के रूप में कार्यरत रहे थे, तथा डॉ. फारुख अब्दुल्ला के, शेख अब्दुल्ला का उत्तराधिकारी बनने से लेकर अब तक, बहुत नजदीकी मित्र रहे हैं।

■ उनका (दुलत साहब का) शुरू से मानना है कि, डॉ. फारुख अब्दुल्ला, अपने पिता कि भांति पूर्णतया भारत के प्रबलतम समर्थक रहे हैं। पर शेख अब्दुल्ला व डॉ. फारुख में एक प्रमुख फर्क था। शेख अब्दुल्ला, कई मसलों पर दिल्ली की केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध आन्दोलनरत भी रहे, तथा कई साल जेल में भी रहे, पर डॉ. फारुख अब्दुल्ला सदा केन्द्रीय सरकार के साथ मिलकर ही काम करने में विश्वास रखते रहे हैं।

■ शायद, दुलत साहब अपनी किताब में डॉ. अब्दुल्ला के इस व्यक्तित्व को भी प्रस्तुत करने जा रहे थे।

डॉ. अब्दुल्ला ने इस पुस्तक के लेखक, अपने पूर्व मित्र तथा जासूस से स्वयं को दूर कर लिया है तथा इस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रावधानों के धारा 9 तथा 14 के तहत कार्डसिल तथा बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक, जिसमें वक्फ बाय यूज़र भी शामिल है, चाहे अधिसूचना के जरिये घोषित किया गया हो, या रजिस्ट्रेशन द्वारा, चिन्हित नहीं किया जायेगा, और न उसका स्वरूप या प्रकार ही बदला जायेगा। हमने यह कथन रिकॉर्ड पर ले लिया है। सात दिन के अन्दर, प्रतिवादियों की ओर से जवाब/काउन्टर ऐफिडेविट पेश हो जाना चाहिये। उसके बाद, पाँच दिन के अन्दर उसका जवाब पेश हो जाना चाहिये।”

बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वह संशोधित वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर स्टे लगा सकता है इसमें वे प्रावधान शामिल हैं, जो वक्फ बाय यूज़र्स, वक्फ बोर्ड और कार्डसिल के गैर मुस्लिमों को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अजमेर दरगाह विवाद पर सुनवाई रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर

जयपुर, 17 अप्रैल। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर अजमेर की निचली अदालत में पेश दावे पर सुनवाई रोकने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की

■ गत नवम्बर में सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को पूजा स्थल विवाद पर कार्यवाही जारी नहीं रखने के निर्देश दिये थे। दिसम्बर में अदालत को इसकी जानकारी भी दे दी गई थी पर निचली अदालत ने कार्यवाही जारी रखी।

गई है। खादिमों की संस्था, अंजुमन सैयद जादगान की ओर से दायर इस याचिका पर आज जस्टिस विनोद कुमार भारवाजी ने एक सप्ताह के लिए सुनवाई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)